मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहुंचने का पूरा श्रेय सोनिया गांधी को दिया, कहा- हर मौके पर मिला उनका साथ

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए अपने चुनाव का श्रेय पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पूरे राजनीतिक करियर में लोगों की सेवा करने के लगातार मौके दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि यह मेरा 13वां चुनाव है। मैं सोनिया गांधी का आभारी हूं। उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने के मौके दिए हैं। खड़गे उन चार उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्हें कल कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। नाम वापस लेने की समय-सीमा खत्म होने के बाद नतीजे की पुष्टि हुई, क्योंकि चार खाली सीटों के लिए मुकाबले में केवल चार उम्मीदवार ही बचे थे, जिससे 18 जून को होने वाली वोटिंग की जरूरत नहीं रही।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 216 ● नई दिल्ली ● शनिवार 13 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

क्या है संविधान का अनुछेद 329, जिसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन खारिज करने के रिटर्निंग आफीसर के आदेश को चुनौती देने वाली मीनाक्षी नटराजन की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट दी है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और एएस चंदुरकर की पीठ ने संविधान के अनुछेद 329 के प्रतिबंध का हवाला देते हुए अनुछेद 32 के तहत दाखिल की गई नटराजन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, प्रतिपक्षी वकील मुकुल रोहतगी, कनु अग्रवाल, चुनाव आयोग की ओर से डीएस नायडू व मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तुषार मेहता की दलीलें सुनीं।

कांग्रेस ने क्या दिया था तर्क?

अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग आफीसर के नामांकन खारिज करने के आदेश को गलत ठहराते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33ए कहती है कि दो साल से अधिक सजा वाले अपराध या जिन आपराधिक मामलों में अदालत ने आरोप तय कर दिये हों उनका ब्योरा हलफनामे में देना होगा। लेकिन जिस केस का खुलासा न करने के लिए रिटर्निंग आफीसर ने नामांकन रद्द किया है उसमें अदालत से आरोप तय नहीं हुए हैं। न ही अदालत ने संज्ञान लिया है अभी सिर्फ कोर्ट ने एक निजी शिकायत पर उन्हें समन जारी किया है।

क्या बोले बीजेपी के वकील?

जबकि प्रतिवादी बीजेपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना विधायी अधिकार है यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में इस संबंध में अनुछेद 32 के तहत दाखिल रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि अनुछेद 32 के तहत याचिका मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर दाखिल की जाती है। रोहतगी का कहना था कि ऐसी किसी भी याचिका पर सुनवाई करने पर अनुछेद 329 स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम के मुताबिक हलफनामे में सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा देना होता है सिर्फ उन मामलों का नहीं जिनमें आरोप तय हुए हों। हालांकि अनुछेद 32 के तहत दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई पर सिंघवी की दलील थी कि अगर नामांकन खारिज करने में स्पष्ट रूप से गलती हुई है तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए अनुछेद 32 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई कर आदेश दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिंघवी की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर सिंघवी की दलीलें स्वीकार की जाती हैं तो इसका मतलब है कि जिन मामलों में नामांकन खारिज होने में स्पष्ट गलती है

तो कोर्ट उन्हें अनुछेद 32 और 226 के तहत दाखिल याचिकाओं में सुन सकता है, और जहां नामांकन खारिज होना पहली निगाह में स्पष्ट तौर पर उतना गलत नहीं है उन्हें चुनाव याचिकाओं के लिए भेज दिया जाए, ऐसा करने का मतलब है कि कोर्ट एक ऐसा सिद्धांत तय कर रहा है जिसका जिक्र अनुछेद 329 में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस व्याख्या को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिटर्निंग आफीसर अरविंद शर्मा ने गत नौ जून को मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने नामांकन के साथ दिए गए फार्म 26 के हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित निजी शिकायत के केस का ब्योरा नहीं दिया था। नटराजन ने पहले इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जब चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला तो नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।

तुगलकाबाद में भयानक मंजर - ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में धधकी आग, धुआं पूरी इमारत में फैला; तीन की जान गई

नई दिल्ली ।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुर के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच महिलाएं झुलस गईं। 70 साल की एक महिला समेत दो की गंभीर रूप से घायल हैं। दमकल कर्मियों ने साहसिक बचाव अभियान चलाकर कुल आठ लोगों को इमारत से बाहर निकाला और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, रात करीब 2:31 बजे तुगलकाबाद की गली नंबर-1 स्थित नया तारा अपार्टमेंट के पास एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आग मकान के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में लगी थी। इसके बाद धुआं तेजी से पूरी इमारत में फैल गया और कई लोग अंदर फंस गए। दमकल विभाग के अनुसार, संबंधित इमारत ग्राउंड प्लस पांच मंजिला है और संकरी गली में स्थित होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सुबह तक आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक, आग पर सुबह 3:45 बजे नियंत्रण पा लिया गया था, जबकि सुबह 4 बजे आग पूरी तरह बुझा दी गई। इसके बाद भी इमारत में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी रखा गया।

डीएफएस के अनुसार, पांच महिलाओं को सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि दो महिलाओं और एक पुरुष को सीएटीएस एम्बुलेंस तथा पीसीआर की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पहुंचाया गया। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती दो महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन महिलाओं का उपचार जारी है। वहीं, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक पुरुष ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती दो अन्य महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है

और उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि पार्किंग क्षेत्र में लगी आग से निकला घना धुआं तेजी से ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया, जिससे लोग इमारत में फंस गए। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पंकज (28), उनकी मां गुड्डी (50) और उनकी बहन सोनी (20) के तौर पर हुई है; ये सभी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहते थे। पुलिस ने बताया कि परिवार के दो अन्य सदस्य, पंकज की एक और बहन मोनी (18) और उनकी 70 वर्षीय नानी, गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है।

दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा स्मार्ट और ग्रीन, सड़कों पर जल्द चलेंगी 2,800 इलेक्ट्रिक एसी बसें

नई दिल्ली। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के जरिए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 2,800 नई एयर-कंडीशंड इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. इस पहल का मकसद राजधानी में क्लीन और स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देना है. नई योजना के जरिए कुल 2,800 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 1,400 नौ मीटर और 1,400 बारह मीटर लंबी बसें होंगी. इस दौरान बड़ी बसों को मुख्य और व्यस्त रूट्स पर चलाया जाएगा, जबकि छोटी बसें कॉलोनियों और स्थानीय फीडर रूट्स पर सेवा देंगी. इसके अलावा अगले चरण में 500 सात मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ी जाएंगी, जिनका मकसद लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है. दिल्ली में फिलहाल लगभग 4,300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं. नई बसों के शामिल होने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ेगी. सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर 7,500 तक पहुंचाने का है. इसके अलावा 2028-29 तक राजधानी में कुल बसों की संख्या लगभग 14,000 करने की योजना है. नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से दिल्ली में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर बाहरी इलाकों और रेजिडेंशियल कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इन बसों से यात्रियों को मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बस स्टॉप तक पहुंचना आसान होगा. इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले रूट्स पर बसों की उपलब्धता भी बढ़ेगी. इसके अलावा ट इलेक्ट्रिक बसें सफर को आरामदायक बनाएंगी. इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते इस्तेमाल से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. इस बीच पर्सनल व्हीकल्स पर निर्भरता घटने से ट्रैफिक जाम में कमी और पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. सरकार का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन और एनर्जी एफिसिएंट बनाकर शहर की आबोहवा को बेहतर करना है.

मानसून से पहले दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा, यमुना तट विकास और 101 जलाशयों के पुनर्जीवन पर एलजी सख्त

नई दिल्ली ।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डीडीए की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजधानी में चल रही प्रमुख पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में यमुना तट विकास, यमुना बाजार के पुनरुद्धार, जलाशयों के संरक्षण और मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने डीडीए की चल रही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित और विश्वस्तरीय राजधानी की परिकल्पना के अनुरूप यमुना रिवरफ्रंट विकास परियोजना पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही यमुना बाजार और उससे सटे घाटों के व्यापक पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देते हुए प्रथम चरण के अंतर्गत 101 जलाशयों के पुनर्जीवन कार्यों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया। द्वारका और रोहिणी में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में दिल्ली में विकसित किए जा रहे बड़े सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवाओं, लक्जरी रिटेल और लॉजिस्टिक्स हब से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। एलजी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मानसून की तैयारियों को लेकर भी बैठक में गंभीरता से चर्चा हुई। एलजी ने वर्ष 2026 की डी-सिल्टिंग कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की स्थिति जानी। साथ ही 15 जून से पहले केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह सक्रिय और तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन ही एक सुदृढ़, टिकाऊ और विकसित दिल्ली के निर्माण की आधारशिला है।

जज ने टिंडर पर किया राइट स्वाइप, गंवाए 52 लाख; न्यायिक अधिकारी के आचरण पर अदालत ने किए तीखे सवाल

नई दिल्ली ।

पटियाला हाउस कोर्ट ने टिंडर के जरिए हुई दोस्ती और 52.81 लाख रुपये की ठगी के एक मामले में बड़ा खुलासा किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने न केवल आरोपी दीपक वत्स की जमानत याचिका खारिज कर दी, बल्कि मामले की जांच एजेंसी और हरियाणा में तैनात एक महिला न्यायिक अधिकारी के आचरण पर भी तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि ई-एफआईआर घरेलू सहायिका के नाम पर दर्ज कराई गई थी, जबकि वास्तविक पीड़िता हरियाणा की न्यायिक अधिकारी हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक न्यायिक अधिकारी, जिससे कानून के प्रति पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है, ने खुद सामने आने के बजाय अपनी घरेलू सहायिका के नाम से शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, रिकॉर्ड से दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंधों के संकेत मिलते हैं और यह मामला उन साइबर अपराधों जैसा प्रतीत होता है जिन्हें आमतौर पर हनी ट्रैप कहा जाता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई।

कोर्ट ने कहा कि अब तक पीड़िता के मोबाइल फोन से पूरी व्हाट्सएप चैट, टिंडर चैट हिस्ट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं। आरोपी दीपक वत्स ने भी अपना मोबाइल पासवर्ड देने से इनकार कर दिया, जिससे जांच प्रभावित हुई। अदालत ने पांच लाख रुपये की नकद राशि पर भी सवाल उठाए, जो हरियाणा के नारनौल में न्यायिक अधिकारी के अदालत कर्मचारी द्वारा जमा कराई गई थी। कोर्ट ने कहा कि धन के वास्तविक स्रोत की स्वतंत्र जांच जरूरी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने जांच अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी दीपक वत्स ने टिंडर पर खुद को गुप्त सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर न्यायिक अधिकारी से संपर्क किया। बाद में निवेश और अन्य बहानों से उन्होंने 52.81 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। आरोपी का दावा है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे और पैसे स्वेच्छा से दिए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अभी जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन जांच में पाई गई कमियों पर भी सख्त टिप्पणी की।

सम्पादकीय...

कॉकरोच है साहब!

अब ये क्या बात हुई? मोदी जी के विरोधी कहते फिर रहे हैं कि ये तो कॉकरोच से डर गए। छप्पन इंच की छाती भी जरूर इनकी झूठी शेखी थी, सिर्फ दिखावे की चीज थी, इनके बाकी तमाम दावों की तरह। वर्ना कॉकरोच से यूं नहीं डर जाते। छप्पन क्या छत्तीस इंच की छाती वाले भी कम से कम कॉकरोच से तो नहीं ही डरते हैं। और तो और खुद मोदी जी की अपनी पार्टी के निचले से निचले, बिचले कार्यकर्ता तक कॉकरोच से नहीं डरते हैं। देखा नहीं कैसे जब कॉकरोचों की पार्टी खबरों में ज्यादा जगह घेरती नजर आ रही थी, तो कर्नाटक में मोदी जी की पार्टी के बिचले कार्यकर्ता टीवी कैमरों के सामने कॉकरोच मारकर दिखा रहे थे, ताकि बाकी सारे कॉकरोच समझ जाएं कि मोदी जी से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है? बेशक, बेचारे मोदी भक्तों को तब कैमरे के सामने कॉकरोच मारने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। कॉकरोचों को डिब्बे से निकाल कर जब तक उन्होंने काला हिट छिड़का, तब तक ज्यादातर कॉकरोच कैमरे के सामने उन्हें और मोदी जी को भी मुंह चिढ़ाकर भाग चुके थे। पर इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि वे कॉकरोच मार पाए कि नहीं मार पाए। भक्त लोग तो वैसे भी आम तौर पर अहिंसक होते हैं। माने मारने से डरते नहीं हैं। इंसानों की लिंचिंग-विंचिंग तो खूब ही करते हैं। पर वह भी अंधाधुंध नहीं, जाति और धर्म देखकर करते हैं। देखते-देखते भी कभी कोई 'मिस्टेक' हो जाए तो बात दूसरी है। आखिर, गलती इंसान से ही होती है। वैसे भी इंसान हो कि जानवर, शिकार भी खाने की चीजों का ही करता है। कॉकरोच कौन खाता है, जी? नहीं है भक्तों की आदत, नहीं मरे उनके मारे कॉकरोच। मगर कैमरे पर यह तो साबित हो गया कि मोदी जी के सिपाही कॉकरोच से नहीं डरते हैं। आखिर, भक्तगण कैमरे की गवाही में मारने के लिए कॉकरोच घर से पकड़ कर लाए थे। मोदी जी कॉकरोच से फिर भी डर गए! इनसे कोई पूछे कि मोदी जी के कॉकरोच से डरने का क्या कोई सबूत है? पहले कह रहे थे कि मोदी जी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कॉकरोच पार्टी के सारे एकाउंट बंद करा दिए, यानी मोदी जी डर गए। आइटी सैल से लेकर, आरएसएस तक, सब कॉकरोचों को विदेशी, पाकिस्तानी, एंटीनेशनल, अराजक वगैरह बताने पर लगा दिए, यानी मोदी जी डर गए। कॉकरोच इन चीफ, दिपके के घर पर पुलिस वाले लगा दिए और उसके घरवाले बुरी तरह डरा दिए, यानी मोदी जी डर गए। गोदी मीडिया के सारे खबरचियों, खास-खास कॉकरोचों की जन्मपत्री खोजने और विदेशी-विरोधी षडयंत्र खोजने में लगा दिए, यानी मोदी जी डर गए। और यह तब था जब तक कॉकरोच सिर्फ साइबर स्पेस में थे। पर अब, जब कॉकरोच साइबर स्पेस से उतर कर, इस धरती पर आने लगे, जब कॉकरोच राजधानी में जंतर-मंतर पर जुटने का मंसूबा बनाने लगे, जब कॉकरोच इन चीफ दिपके के पांव दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पड़ने लगे, जिसके नाम में अभी तक इंदिरा गांधी शब्द जुड़ा हुआ है, तब? मोदी जी के वही विरोधी कह रहे हैं कि दिपके को हवाई अड्डे पर ही नहीं रोका, यानी मोदी जी डर गए। हवाई अड्डे पर दिपके को लेने के लिए बहुत से कॉकरोचों को जमा होने दिया, यानी मोदी जी डर गए। दिपके को हवाई अड्डे पर ही बुलाकर, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर जमावड़े की इजाजत दी, यानी मोदी जी डर गए। जंतर-मंतर पर कॉकरोचों की भीड़ जमा हो जाने दी, यानी मोदी जी डर गए। कॉकरोचों को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने और अगले हफ्ते फिर लौटने की धमकी देने के बाद, शांति से घर जाने दिया, यानी मोदी जी डर गए। पर सच बताइए, इस सबमें से कोई भी सचमुच मोदी जी के डरने का सबूत है क्या? उल्टे मोदी जी के विरोधी तो अपनी ही बात को काट रहे हैं। पहले कह रहे थे कि साइबर स्पेस में कॉकरोचों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं यानी मोदी जी डर गए। अब कह रहे हैं कि इस धरती पर कॉकरोचों को दुलराने की कोशिश कर रहे हैं यानी मोदी जी डर गए। सबूत की बात छोड़िए, मोदी जी के विरोधी पहले यह तो तय कर लें कि मोदी जी कॉकरोचों को दबा रहे हैं या दुलरा रहे हैं। अब एक नजर न कॉकरोच न विपक्ष, मोदी जी के किसी से भी नहीं डरने के सबूत पर डाल लीजिए--धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री हैं और मोदी जी की कृपा हुई तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद भी, शिक्षा मंत्री बने रहेंगे! राजनाथ सिंह ने तो ग्यारह साल पहले ही बता दिया था--मोदी राज में इस्तीफे नहीं होते। पब्लिक के मांगने से इस्तीफे हर्गिज नहीं होते। बस प्रभु अपनी कृपा ही समेट लें तो मंत्रिमंडल से छुट्टी का रिवाज जरूर है, पर इस्तीफे का नहीं। बारह साल में एक भी खुली प्रेस कान्फ्रेंस नहीं करने के लिए, प्रेस से मोदी जी का डर तो सब को दिखाई देता है, पर बारह साल में एक भी इस्तीफा नहीं होने देने की, मोदी जी की निडरता किसी को क्यों याद नहीं रहती है? सच्ची बात यह है कि मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं। दूसरे जिस-जिस से डरते हैं, उससे तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। तस्वीर तो देखी होगी--इस पार मोदी जी, उस पार शेर और मोदी जी शेर से आंखों में आंख डालकर बात करते हुए; बीच में सिर्फ एक कांच के पर्दे की दूरी। जो मर्द खूंखार शेर से नहीं डरता वह किसी और से क्या डरेगा? झूठे वादे करने से, हवाई दावे करने से, नागपुरी व्हाट्सएप ज्ञान पेलने से, सच को तोड़ने-मरोड़ने से, दोस्तों, भक्तों और गोदी सवारों को निभाने से, हिंदू-मुसलमान करने से, मोदी जी डरने की तो बात दूर रही, कभी झिझके तक नहीं। हां! टेलीप्राम्प्टर ही दगा दे गया हो, तो बात दूसरी है। यह भी कोरी अफवाह है कि मोदी जी जेन ज़ी से डरते हैं। कहीं, यहां भी श्रीलंका जैसा नहीं हो जाए। कहीं यहां भी, बांग्लादेश जैसा नहीं हो जाए। चुनाव आयोग, अदालत, संसद, ईडी, सीबीआई, नौकरशाही, यूनिवर्सिटी, राष्ट्र सेठ सब की सैटिंग कहीं धरी की धरी नहीं रह जाए। ऐसा न हो नागपुर-वागपुर, मंदिर-वंदिर कोई काम नहीं आए। सब झूठ। और मजा कि यह चीफ जस्टिस जी ने कहा है, फिर भी यह कोरी अफवाह है कि कॉकरोच और जेन ज़ी चूंकि एक समान हैं, इसलिए मोदी जी कॉकरोच से डरते हैं। जेन ज़ी, कॉकरोच की तरह कहीं से भी निकल आते हैं। एक बार निकलना शुरू हो जाएं तो निकलते ही जाते हैं। न दबाने से दबते हैं, न मारने से मरते हैं और न भगाने से भागते हैं। कॉकरोच तो बहाना है, विरोधियों को तो मोदी जी को जेन ज़ी से डराना है। पर सब झूठ। जेन ज़ी से मोदी जी क्यों डरने लगे। जेन ज़ी से तो मोदी जी का पुराना रिश्ता है। मोदी जी के तो नाम में ही जी लगा हुआ है। बस, कॉकरोच ही मोदी जी को पसंद नहीं है। कितना गंदा तो लगता है, देखने में ही। कहीं भी पहुंच जाता है। पसंद क्या, मोदी जी को कॉकरोच देखना भी बर्दाश्त नहीं है, विरोध की तरह, सवाल की तरह, सच की तरह। अब विरोधी इसे कॉकरोच से डरना मानना चाहें तो वही सही। क्या कहेंगे, यही ना कि मोदी भी कॉकरोच से डरता है।

नरसंहार गुलाम कश्मीर में

भारत की आजादी के तुरन्त बाद से ही जिस तरह पाकिस्तान ने सीमावर्ती रियासत जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण करके वहां की आम रियाया पर मनघोर अत्याचार और बर्बरता अपने कथित कबायलियों को भेज कर की थी उससे स्पष्ट हो गया था कि 15 अगस्त, 1947 को भारत को काट कर बने इस नये मुल्क पाकिस्तान के इरादे जम्मू-कश्मीर को अपना गुलाम बनाने के हैं। कबायलियों के वेष में पाकिस्तानी फौज के सैनिकों ने इस आक्रमण को विस्तृत रूप देना शुरू किया तो रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह के होश उड़े और उन्होंने 26 अक्टूबर, 1947 को अपनी पूरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया और इसके बाद भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना शुरू किया और उसे पीछे धकेलना जारी रखा परन्तु इसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत के राष्ट्रसंघ में पहुंच जाने की वजह से युद्ध विराम की घोषणा हो गई और दोनों फौजें अपने-अपने स्थान पर स्थिर हो गईं। अतः जम्मू-कश्मीर रियासत का एक-तिहाई से भी अधिक इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रह गया जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर या गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कह कर शेखी बघारता है। मगर इसके बाद से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के लिए जो नीतियां अपनाईं वे पूरी तरह मानवाधिकार विरोधी व आम लोगों को उनके लोकतान्त्रिक हकों से महरूम रखने वाली थीं। कहने के लिए पाकिस्तान ने यहां एक कश्मीर एसेम्बली का गठन किया जिसकी 45 सीटें हैं मगर धीरे-धीरे इस इलाके में अपने देश के दूसरे राज्यों के लोगों को बसाना शुरू किया और इस क्षेत्र का पूरा प्रशासन भी इन्हीं लोगों के हाथों में देने के मंसूबे बनाये। जिसके चलते आज 78 वर्षों बाद गुलाम कश्मीर की हालत यह हो गई है कि कश्मीरी भाषा से लेकर कश्मीरी संस्कृति तक इस इलाके से गायब होने लगी है और स्थानीय मूल नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

पाकिस्तानी हुक्मरानों ने गुलाम कश्मीर में अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए यहां की एसेम्बली में 12 सीटें भी गैर कश्मीरियों के लिए आरक्षित कर दी हैं जिससे इस क्षेत्र के प्रशासन के हर अंग पर उनका कब्जा रह सके और उनकी मर्जी के बिना न तो चुना हुआ कोई सदर बन सके और न प्रशासनिक मुखिया। पाकिस्तान की इन नीतियों के विरुद्ध क्षेत्र की जनता पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है मगर हर बार पाकिस्तान की सरकार पुलिस व सेना का बल प्रयोग कर जन आन्दोलन को कुचल देती है। मगर पिछले दो दिनों से गुलाम कश्मीर में पाक फौज और पुलिस द्वारा जिस बर्बर और नंगेजी तरीके से यहां की आम जनता पर जुल्म ढहाये जा रहे हैं उसने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार 100 से अधिक नागरिकों को गोलियों का शिकार बना दिया गया है और 200 से अधिक को जख्मी कर दिया गया है।

अतः जम्मू-कश्मीर रियासत का एक-तिहाई से भी अधिक इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रह गया जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर या गुलाम कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कह कर शेखी बघारता है। मगर इसके बाद से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के लिए जो नीतियां अपनाईं वे पूरी तरह मानवाधिकार विरोधी व आम लोगों को उनके लोकतान्त्रिक हकों से महरूम

इसके बावजूद पूरे पाक अधिकृत कश्मीर की जनता सड़कों पर है और वह हुक्मरानों के अत्याचारों का विरोध कर रही है। इससे पता चलता है कि गुलाम कश्मीर में मानवाधिकारों का पूरी तरह हनन हो रहा है और प्रशासन दमनकारी चक्र चला रहा है। दरअसल क्षेत्र की जनता ने एक संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी बना कर सरकार का विरोध करना शुरू किया। इस कमेटी में नागरिक समाज के सभी तबके के लोग शामिल हैं और वे लम्बे समय से बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, भ्रष्ट प्रशासन और स्थानीय लोगों की राजनीतिक उपेक्षा के विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। इस आन्दोलन की प्रमुख मांग यह भी है कि एसेम्बली में गैर कश्मीरियों के लिए जो 12 सीटें आरक्षित की गई हैं वे समाप्त की जायें। मगर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी को ही प्रतिबन्धित करने की घोषणा कर दी जिसके खिलाफ आम लोगों में रोष पैदा हो गया और विगत मंगलवार से इस प्रतिबन्ध के खिलाफ जनआन्दोलन शुरू करने की घोषणा की। मगर इस आन्दोलन के आह्वान के बाद बीते रविवार को एक्शन कमेटी के दो नेताओं का फौज व पुलिस ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी गई। इन नेताओं के शव गुलाम कश्मीर के शहर रावलकोट के अस्पताल में रखे हुए थे। आन्दोलनकारियों ने तब रावलकोट अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां से फौज ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की जिसका प्रतिरोध करने पर उन पर गोलियों की बरसात बेतरतीब तरीके से की गई। अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों द्वारा इसे नरसंहार की संज्ञा भी दी जा रही है। यह हिंसा का दौर बीते दिन तक जारी था। इसके खिलाफ एक्शन कमेटी ने पूरे गुलाम कश्मीर में बन्द का आह्वान भी कर रखा है। जिसके चलते प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में इंटरनेट ही बन्द कर दिया है। बन्द के आह्वान से रावलकोट के अलावा इस क्षेत्र की राजधानी मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, ततापानी और पादरी जैसे शहरों में आन्दोलन भड़क उठा है जिसे रोकने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिये हैं। अतः बहुत साफ है कि गुलाम कश्मीर के मूल निवासियों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखने के उपाय प्रशासन द्वारा किये जा रहे हैं जिसका संज्ञान दुनिया के उन देशों सहित राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार संरक्षक संगठन द्वारा भी लिया जाना चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें नागरिकों का मौलिक हक मानते हैं। अभी तक केवल ब्रिटेन की संसद के 30 सदस्यों ने पाकिस्तान विरोधी प्रस्ताव रखा है। जहां तक भारत का सवाल है तो वह शुरू से ही मानता है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अटूट हिस्सा है और इसी कारण से उसने अपनी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें गुलाम कश्मीर के लोगों के लिए खाली छोड़ रखी हैं लेकिन अब यह अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी को ही देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर जुल्म ढा रही है और उनके नागरिक अधिकारों को कुचल रही है। दूसरी तरफ भारत के जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारतीय संविधान के तहत मिले नागरिक अधिकारों से पूरी तरह लैस कर दिया गया है और उन्हें अपने विकास के लिए सभी प्रकार के साधन मुहैया कराये जा रहे हैं।

हम अंधभक्त.....

सरकार जी ने एक सलाह दी और उस पर हमने अमल भी किया। हालांकि सरकार जी ने स्वयं अमल नहीं किया पर हमने किया। सरकार जी ने जिस दिन सलाह दी उसके अगले दिन ही उसे तोड़ दिया। सलाह दी कि विदेश यात्रा न करें और अगले दिन ही विदेश यात्रा पर चले गए। सरकार जी भी विदेशी नेताओं से वर्चुअल मीटिंग कर सकते थे पर पर वर्चुअल मीटिंग में वह सुख कहाँ जो आमने सामने की मीटिंग में है। वर्चुअल मीटिंग में न तो जोर्जे जैसी भद पिटती है और न ही इटली में मेलोडी देने जैसा सुख मिलता है। सरकार जी की यह पुरानी आदत है। लोगों को उपदेश देना पर खुद नहीं मानना। खैर, राजा और प्रजा के आचरण में फर्क होना ही चाहिए। यह मेरा नहीं, सरकार जी का मानना है। सरकार जी स्वयं विदेशी चश्मा, विदेशी पेन, विदेशी घड़ी, विदेशी जैकेट पहन कर प्रजा को स्वदेशी अपनाने की सलाह देते हैं। जबकि इनमें से कुछ चीजें हमारा देश भी अच्छे बना रहा है। साइन तो दस बीस रुपये वाले बॉल पेन से ही अच्छे होते हैं, बशर्ते करने आते हों।पर मैं उन लोगों में से हूँ जो सरकार जी की दी गई सारी सलाह मानते हैं। सरकार जी उन सलाहों को खुद माने या न माने, मैं अवश्य मानता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार घूमने विदेश नहीं जाऊंगा। और मैं तो एक बार को सरकार जी की सलाह नहीं भी मानू पर श्रीमती जी एक दम देशभक्त हैं। जब से सरकार जी ने सोना नहीं खरीदने की सलाह दी है, मजाल है जो हमारे घर में एक ग्राम भी सोना आ गया हो। उससे पहले तो हम हर रोज सुनार जी की दुकान पर बैठे रहते थे और कम से कम पांच दस तोला सोना खरीद कर ही उठते थे। तो परिवार समेत यहीं आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाया। सरकार जी के हम बहुत बड़े भक्त हैं। सचमुच में बड़े वाले। अरे वही जिन्हें आप अंधभक्त कहते हैं ना, वही। कोरोना काल में सरकार जी के कहने पर बरतन भांडे भी बजाये और मोमबत्ती भी जलाई। गोमूत्र पीने की भी कोशिश की पर उसकी सुगंध (दुर्गन्ध लिखने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं किसी की भावनाएं न आहत हो जाएं) न तो नाक बर्दाश्त कर पाई और न ही दिमाग। गोबर भी लपेटा पर एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही बाँह पर लपेटा। उस बाँह पर इतनी खुजली हुई और फोड़े फुंसी उगीं कि सारे शरीर पर पोतने का साहस ही नहीं हुआ। हाँ, इसका एक लाभ अवश्य हुआ। कोरोना काल में मैं तीन बार कोरोना से संक्रमित हुआ पर उस बाँह को कोविड नहीं हुआ। तो गर्मियां शुरू हुईं। बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बनना शुरू हुआ तो सरकार जी की सलाह आ गई। फिर तो देश में ही घूमने का कार्यक्रम बनाना था। वैसे मन विदेश जाने का था पर क्या करें ऐन वक्त पर सरकार जी की सलाह आ गई। और सलाह क्या, मानो आदेश था। तो हमने देश में ही घूमने का प्रोग्राम बना लिया। जाने के लिए जगह भी चुन ली। प्रोग्राम क्या बनाया, जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़े। प्रोग्राम बनाने और उसे कार्यान्वित करने के बीच में ही तीन बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए। हमारी यह खुशी कि सरकार जी इतने अच्छे हैं कि खाड़ी युद्ध के बावजूद तेल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्षण भर में काफूर हो गई। समझ में आया कि वह सरकार जी की अच्छाई नहीं, चुनाव की महिमा थी कि पेट्रोल डीज़ल के दाम नहीं बढ़ रहे थे। खैर, ओखली में सिर दिया है तो मूसल का क्या डर। जब सरकार जी को चुना है तो महंगाई का क्या रोना।

ईरान नें होर्मुज जलडमरूमध्य बंद से ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बन गया है। 11 जून 2026 को स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दुनियाँ के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य, को सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद करने की घोषणा कर दी। ईरानी सैन्य नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। यह कदम कथित रूप से अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री टकराव तथा अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के बाद उठाया गया है। इसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी बेचैनी फैल गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 95.40 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई लगभग 92.6 डॉलर प्रतिबैरल तक पहुंच गया है। दुनियाँ की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, इसलिए इस घटनाक्रम ने ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताव्यक्त की है। वर्तमान घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही है कि होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा व्यवस्था की धुरी माना जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री मार्ग सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक और ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों के निर्यात का मुख्य रास्ता है। सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन करोड़ों बैरल तेल और विशाल मात्रा में एलएनजी इसी मार्ग से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है। यही कारण है कि जब भी इस जलमार्ग में व्यवधान आता है, उसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर दिखाई देता है। वर्तमान संकट में भी निवेशकों और ऊर्जा कंपनियों ने आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए तेल खरीदना शुरू कर दिया,जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल उछाल देखने को मिला। साथियों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहली प्रतिक्रिया तेल कीमतों में तेजी के रूप में सामने आई है। ब्रेंट क्रूड लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया है जबकि डब्ल्यूटीआई भी 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि यदि जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है या सैन्य संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर भी जा सकती हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ने की आशंका है क्योंकि ऊर्जा लागत लगभग हर आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती है।साथियों, भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है और उसका एक बड़ा भाग होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। इसलिए इस मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट का सीधा असर भारतीय ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। यदि तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा,चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव पड़ सकता है। ऊर्जा आयात पर बढ़ती लागत अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और महंगाई को बढ़ावा देती है।सबसे पहला प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से भारतीय तेल विपणन कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। यदि मौजूदा तनाव कुछ और दिनों या सप्ताहों तक बना रहता है तो पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लंबी अवधि तक ऊंचे तेल मूल्य बने रहने पर ईंधन की कीमतों में कई रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा असर आम नागरिकों, किसानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा।पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का साधन नहीं हैं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं। डीजल की कीमत बढ़ने का अर्थ है कि ट्रकों, बसों और मालवाहक वाहनों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी। जब परिवहन महंगा होता है तो फल, सब्जियां, दूध, अनाज, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि तेल कीमतों में वृद्धि को अक्सर 'महंगाई की जननी' कहा जाता है। एक बार यदि ईंधन लागत बढ़ती है तो उसका असर अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में सटीकता से दिखाई देता है। साथियों, 7 जून 2026 से मृग लग गया है व खेती के कार्य शुरू हो चुके हैं,कृषि क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। भारत में सिंचाई, कृषि मशीनरी और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है। डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ेगी और इसका असर खाद्यान्न कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर है। यदि ऊर्जा लागत बढ़ती है तो उर्वरकों का उत्पादन भी महंगा हो सकता है।विमानन क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है। विमान ईंधन की लागत एयरलाइंस के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होती है। यदि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए में वृद्धि संभव है। इससे पर्यटन उद्योग, व्यापारिक यात्राओं और विमानन क्षेत्र की मांग पर असर पड़ सकता है। साथियों, भारत के लिए चिंता का एक और बड़ा विषय एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति है।

भारत कतर सहित खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में एलएनजी आयात करता है और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। यदि इस मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान रहता है तो सीएनजी और पीएनजी की उपलब्धता तथा कीमतों पर असर पड़ सकता है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ- साथ बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की लागत भी बढ़ सकती है।हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन भारत पूरी तरह असहाय नहीं है। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं जिनका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में किया जा सकता है।विशाखापट्टनम मैंगलोर और पादुर जैसेस्थानों पर स्थापित भूमिगत भंडारण सुविधाएं सीमित अवधि के लिए देश को राहत प्रदान कर सकती हैं। ये भंडार किसी भी अचानक आपूर्ति संकट के दौरान महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं।इसके अतिरिक्त भारत नेऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई है। रूस से बढ़ते तेल आयात ने भारत को एक वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत उपलब्ध कराया है। रूस से आने वाला तेल सामान्यतः अन्य समुद्री मार्गों से आता है, इसलिए होर्मुज संकट की स्थिति में यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। यदि आवश्यकता हुई तो भारत रूस तथा अन्य गैर-खाड़ी आपूर्ति कर्ताओं से आयात बढ़ाने की दिशा में सटिका से कदम उठा सकता है। साथियों, सऊदी अरब,यूएई और अन्य खाड़ी देशों के पास भी कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन मार्ग उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से सीमित मात्रा में तेल निर्यात किया जा सकता है। हालांकि ये मार्ग होर्मुज के पूर्ण विकल्प नहीं हैं, फिर भी वे वैश्विक बाजार में आपूर्ति के पूर्ण ठहराव को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसी कारण ऊर्जा बाजारों में अभी भी आशा बनी हुई है कि राजनयिक प्रयासों के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।भू-राजनीतिक दृष्टि से यह संकट केवल तेल या गैस तक सीमित नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व समुद्री व्यापार के सबसे संवेदनशील मार्गों में से एक है। इसके बंद होने से बीमा लागत, माल ढुलाई शुल्क और शिपिंग समय में वृद्धि होती है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही आपूर्ति व्यवधानों का अनुभव कर चुकी है; ऐसे में होर्मुज संकट नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। साथियों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते हमले और समुद्री असुरक्षा वैश्विक व्यापार तथा भारतीय नागरिकों दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों, व्यापारिक जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी किस काम के?

अनिल जैन

यह बड़ा सवाल है कि व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले तीन पहचान पत्रों- आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी का क्या काम रह गया है? सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मसले पर दायर याचिकाओं का निबटारा करते हुए कहा कि ये तीनों पहचान पत्र किसी की नागरिकता प्रमाणित नहीं करते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है। इन तीनों के दम पर कोई व्यक्ति देश का मतदाता भी नहीं बन सकता है। अभी किसी के पास मतदाता पहचान पत्र है, जिसके दम पर उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला है लेकिन इसके दम पर अब वह मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा सकता है। ऐसा पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में हुआ है और अब जिन 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है वहां भी ऐसा ही होगा। लोगों ने कितनी कवायद की थी आधार बनवाने के लिए। अब भी अगर किसी को आधार में कोई बदलाव कराना होता है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही वोटर आई कार्ड बनवाना भी आसान काम नहीं होता है। लोगों ने मेहनत करके सब बनवाया लेकिन अब इनके दम पर मतदाता सूची में नाम नहीं शामिल हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट है कि इन तीन में से किसी एक या तीनों दस्तावेज होने के बावजूद कोई अन्य दस्तावेज देना होगा तब जाकर मतदाता सूची में नाम शामिल होगा।

भारत का शेयर बाजार सातवें स्थान पर लुढ़का

भारत के शेयर बाजार का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। अब यह खिसक कर सातवें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले दिनों खबर आई थी कि ताइवान की सिर्फ एक कंपनी टीएसएमसी का बाजार मूल्य बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के बाजार मूल्य से ज्यादा हो गया है। जाहिर है जब एक कंपनी का मूल्य ही पूरे शेयर बाजार से ज्यादा हो जाएगा तो उस देश का पूरा शेयर बाजार तो आगे निकलेगा ही। सो, ताइवान के शेयर बाजार का मूल्य भारत के शेयर बाजार से ज्यादा हो गया। इसके बाद खबर आई कि दक्षिण कोरिया का बाजार भी भारत से आगे निकल गया। अमेरिका, जापान, चीन और हांगकांग पहले से ऊपर थे। इन चार देशों के बाद ताइवान और दक्षिण कोरिया आ गए। ताइवान और दक्षिण कोरिया का बाजार सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनियों के शेयरों में आई तेजी की वजह से बढ़ा है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग चिप डिजाइन करने वाली सबसे बड़ी दो कंपनियों में से एक है। अब दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार पांच ट्रिलियन डॉलर का है और ताइवान का शेयर बाजार 5.2 ट्रिलियन डॉलर का है। भारत अब भी चार ट्रिलियन डॉलर के आसपास अटका है। इसका कारण यह है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यही स्थिति रही तो शेयर बाजार की हालत और कमजोर होगी। एआई में पिछड़ने का ही नतीजा है कि भारत में विदेशी निवेश भी नहीं आ रहा है।

सरकार समर्थक अर्थशास्त्री भी चिंतित

सरकार को किसी भी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सलाह देती हैं तो उन्हें राजनीतिक आलोचना कह कर खारिज कर दिया जाता है। राहुल गांधी कई वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उल्टे उन्हें पप्पू ठहराने का अभियान चलता रहता है। लेकिन अब तो सरकार के समर्थक अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि भारत गाथा यानी इंडिया स्टोरी पटरी से उतर गई है और उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। सरकार की नीतियों के समर्थक अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने लगातार दूसरी बार अपने कॉलम में सरकार की नीतियों में कमियां बताई हैं और सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने 'इंडियन एक्सप्रेस' के पिछले कॉलम में कहा था कि भाजपा चुनाव जीत रही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। अब ताजा कॉलम में उन्होंने इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जिस सुधार की जरूरत थी वह नहीं किया गया है। उन्होंने खासे 2014 के बाद यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की विफलताओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में भारत और इंडोनेशिया की कहानी शुरू हुई थी। इंडोनेशिया ने ऐसे सुधार किए, जिससे उसे निवेश मिला और सम्मान भी मिला, जबकि भारत ने जरूरी सुधार नहीं किए, जिससे पूंजी निकल कर बाहर गई और दुनिया से भारत को अवमानना मिली।

भाजपा के हर काम में देरी

भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा का तीन साल का कार्यकाल छह साल तक चला। बाद के तीन साल तो वे वैसे ही सेवा विस्तार पर चले, जैसे सीबीआई और ईडी के निदेशक और अन्य अधिकारी चलते हैं। छह साल बाद जैसे-तैसे नड्डा की जगह नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो करीब साढ़े चार महीने के बाद भी अभी तक उनकी टीम का गठन नहीं हुआ है। यही हाल दो राज्यों में बनी नई सरकार का है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की और सरकार बनाई लेकिन करीब एक महीने तक मुख्यमंत्री ने सिर्फ पांच मंत्रियों के साथ सरकार चलाई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अकेले 42 विभाग संभालते रहे। बड़ी मशक्कत के बाद वहां मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। 35 नए मंत्री बनाए गए। ऐसे ही असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक महीने तक चार लोगों के साथ सरकार चलाई और एक महीने बाद वहां मंत्रिपरिषद का विस्तार हो पाया। सोचें, अगर ऐसा किसी कांग्रेस शासित राज्य में हो जाता तो भाजपा कितना बड़ा मुद्दा बनाती और मीडिया किस तरह से कांग्रेस पर हमले करता। केरल में कांग्रेस को नेता चुनने में भाजपा के मुकाबले दो दिन का अधिक समय लगा था। लेकिन केरल में कांग्रेस नेता नहीं चुन पा रही है' इस नैरेटिव पर डेढ़ सौ से ज्यादा डिबेट टीवी चैनलों में हुई थी। बहरहाल, इस लिहाज से देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तो फेरबदल की कोई संवैधानिक जरूरत नहीं है। वह तो राजनीतिक जरूरत के लिहाज से किया जाना है।

कोई भी पार्टी जगह नहीं दे रही महिलाओं को

अप्रैल में जब नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का विधेयक संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया था तो ऐसा लगा जैसे भाजपा और उसके नेताओं को महिलाओं की कितनी परवाह है। विपक्षी पार्टियों ने भले ही इसका विरोध किया था लेकिन महिलाओं के प्रति जुबानी जमाखर्च करने में उसने भी कंजूसी नहीं की थी। उसके बाद पांच राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचार के दौरान विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भाजपा अपने को इस बात के लिए प्रतिबद्ध बता रही है कि वह महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसने 294 सीटों में से कुल 33 सीटों पर महिलाओं को उतारा था। यानी करीब 11 फीसदी टिकट महिलाओं को दिए थे। भाजपा को 207 सीटें मिली हैं, जिनमें से 21 महिलाएं हैं। इनमें से सात महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। कुल 41 मंत्री बने हैं, उनमें सिर्फ सात महिलाएं हैं। यानी 20 फीसदी से कुछ कम महिलाओं को मंत्री बनाया गया। इसका अर्थ है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक महिलाओं को 33 फीसदी हिस्सा भाजपा भी नहीं देगी। उधर कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार बनी तो पहले चरण में 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। उनमें एक भी महिला मंत्री नहीं है। यह पूर्वाग्रह की हद है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक अपवाद है। केरल में कांग्रेस की 21 सदस्यों की वीडी सतीशन सरकार में भी सिर्फ दो महिलाएं मंत्री हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

सोनीपत का नागरिक अस्पताल अब होगा 300 बिस्तरों का, हिसार के पनिहार चक में खुलेगा नया उप-स्वास्थ्य केंद्र

चंडीगढ़ ।

हरियाणा सरकार ने राय की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और आम जनमानस को उनके घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में दो बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने सोनीपत स्थित 200 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल की क्षमता को अपग्रेड कर 300 बिस्तरीय करने और हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र पनिहार चक में एक नया उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा करते हुए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी राय के प्रत्येक नागरिक तक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने इन दोनों प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें सोनीपत के अस्पताल का अपग्रेडेशन विशेष रूप से शामिल है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा इस वर्ष के बजटीय सत्र के दौरान की गई थी। सोनीपत के नागरिक अस्पताल की क्षमता में इस विस्तार से स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जिला अस्पताल पर मरीजों का भारी दबाव रहता था, लेकिन अब बिस्तरों की संख्या बढ़कर 300 होने से न केवल गंभीर मरीजों को बेड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अस्पताल में नए वार्डों का निर्माण, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और अतिरिक्त डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का रास्ता भी साफ होगा। इससे मरीजों के परिवारों का आर्थिक व मानसिक बोझ भी घटेगा। इसी तरह ग्रामीण आंचल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कड़ी में हिसार जिले के गांव पनिहार चक को एक बड़ी सौगात मिली है। यहाँ नए उप-स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंजूरी से पनिहार चक सहित इसके आसपास के कई गांवों के लोगों का जीवन आसान होगा।

अब ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सामान्य बीमारियों के इलाज, नियमित टीकाकरण, और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के शहरों या बड़े नागरिक अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें अपने ही गांव में प्राथमिक उपचार और मुफ्त दवाइयां सुलभ हो सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दोहराया कि राय सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का समान रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

मानसून के दौरान गुरुग्राम में इस बार नहीं होगी जलभराव की समस्या, सभी चिन्हित स्थानों पर कराए गए जल निकासी के सुधारात्मक कार्य - राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़ । हरियाणा के उद्योग एवं वाणिय मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार के पास जनहित के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। आमजन केवल नियमों और मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव लेकर आएं, सरकार उनकी समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राव नरबीर कल देर सांय गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के गांव मैदावास तथा धूमसपुर में 16 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास उपरांत आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट हैं। सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम तेजी से विकसित हो रहा शहर है और यहां की आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बरसात के दौरान जलभराव की समस्या वाले 158 स्थानों की पहचान की गई थी। इन सभी स्थानों पर संबंधित विभागों द्वारा विशेष अभियान चलाकर जल निकासी के आवश्यक सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने, नालों की सफाई तथा अन्य आवश्यक कार्यों के कारण इस वर्ष शहरवासियों को जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि विकास केवल सड़कों, भवनों और अन्य परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण अभियान से जुड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति प्रतिदिन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उसे अवशोषित करने के लिए लगभग 14 पेड़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने घरों, खेतों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलना ही समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

आमजन को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में अधिकारी निभाएं जिम्मेदारी - राव नरबीर सिंह

चण्डीगढ़ । हरियाणा के उद्योग, वाणिय, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में अधिकारी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार की सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। राव नरबीर सिंह आज झज्जर में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 10 का मौके पर निपटान किया गया। परिवेदना समिति की बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मानसून सीजन शुरु होने से पहले झज्जर जिला के सभी सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जाए। जहां भी सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, उनकी मरम्मत का कार्य तुरंत प्रभाव से किया जाए। गांव भंभेवा निवासी रामनिवास ने शिकायत रखी कि उनकी गली में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। बेरी के बीडीपीओ ने बताया कि इस कब्जे का हटा दिया गया है। राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए कि भविष्य में दोबारा कब्जा हो तो दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गांव महराना निवासी धर्मबीर सिंह ने बताया कि उनके घरों के आसपास दूषित जलभराव की समस्या बनी हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह में यहां मिट्टी की भरत कर समस्या का निवारण किया जाए। बैठक में गांव डीघल निवासी बुधराम ने बताया कि चार साल पहले उसके भाई का सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। इस मामले में शिकायत की गई तो जिला स्तर पर गठित किए गए बोर्ड से उसकी जांच करवाई गई, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उपायुक्त अपने स्तर पर एक बार इस मामले का परीक्षण करें। मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, पंचायती राज, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बारिश के दौरान किसी गांव में जलभराव ना होने पाए। उन्होंने गांवों के जोहड़ और पंचायती भूमि से नाजायज कब्जे हटवाने के भी निर्देश दिए।

हरियाणा जल्द बनेगा आलू के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए एक नैशनल-हब- श्याम सिंह राणा

-हरियाणा टिशू कल्चर-आधारित बीज आलू अधिनियम, 2026, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) मिशन और हरियाणा उद्यानिकी नीति पर केंद्रित राय स्तरीय कार्यशाला आयोजित

चंडीगढ़ । हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा वैसे तो पहले ही कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में एक अग्रणी राय है और अब यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज आलू के उत्पादन के लिए एक नैशनल-हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। वे आज यहां हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा हरियाणा टिशू कल्चर-आधारित बीज आलू अधिनियम, 2026, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) मिशन और हरियाणा उद्यानिकी नीति पर केंद्रित एक राय स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, बागवानी निदेशालय के विभागाध्यक्ष श्री अर्जुन सैनी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, एफपीओ प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान और बीज आलू उत्पादक मौजूद रहे। श्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रस्तावित हरियाणा टिशू कल्चर-आधारित बीज आलू अधिनियम, 2026 राय में रोग-मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाले और ट्रेस करने योग्य (ट्रेसेबल) बीज आलू के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ नए बाजारों तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश भर में गुणवत्तापूर्ण बीज आलू की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी उपलब्धता अभी भी सीमित है। इस प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य टिशू कल्चर, एयरोपेनिक्स और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बीज आलू उत्पादन के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित करना है, जिससे प्रमाणित बीज उत्पादन और विपणन में किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि हरियाणा में लगभग 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है और राय में बीज आलू उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इस प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने के बाद, राय में शुरुआती वर्षों के भीतर लगभग 10 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज आलू उत्पादन करने की क्षमता विकसित हो सकती है; इससे न केवल राय की अपनी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि अन्य रायों को भी गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की जा सकेगी। इस कार्यशाला में एफपीओ मिशन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने समझाया कि सामूहिक विपणन, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), भंडारण और मूल्यवर्धन (वैल्यू एडिशन) जैसी सुविधाएं प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने में एफपीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राय सरकार एफपीओ को सशक्त बनाने और उन्हें कृषि व्यवसाय से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक बागवानी, संरक्षित खेती, उच्च मूल्य वाली फसलों और निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यानिकी नीति के तहत किसानों को मिलने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, एफपीओ सदस्यों और प्रगतिशील किसानों ने प्रस्तावित अधिनियम पर अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए। विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम को अधिक प्रभावी और किसान-अनुकूल बनाने के लिए प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

प्रबुद्धजनों के सुझावों से और मजबूत होगा विकसित भारत का संकल्प - राव इंद्रजीत सिंह

(संवाददाता)

चंडीगढ़ । केंद्रीय राय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रबुद्धजनों, विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके सुझावों और अनुभवों से देश के विकास को नई दिशा और गति मिलती है। केंद्रीय राय मंत्री ने शुक्रवार को गुरुग्राम में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेक्टर-17 स्थित ब्लिस प्रीमियर गार्डन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन व्यवस्था स्थापित की है। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

सम्मेलन में उद्योग, शिक्षा, खेल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित प्रबुद्धजनों से विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों और विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव भी आमंत्रित किए। चर्चा के दौरान उपस्थित बुद्धिजीवियों ने देश में आधारभूत ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार, डिजिटल क्रांति, कर प्रणाली में सुधार तथा जीएसटी व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कौशल विकास तथा नागरिक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विचार एवं सुझाव भी साझा किए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी साकार होगा जब सरकार और समाज मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा देशवासियों के सहयोग से भारत आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी शक्तियों में और अधिक मजबूती के साथ अपनी पहचान स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम में महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क (लेजर वैली) में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इसके उपरांत केंद्रीय राय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा गुरुग्राम में सेक्टर-14 स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नागरिकों को दी जा रही परामर्श एवं जांच सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य जांच करवाने पहुंचे नागरिकों तथा स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले युवाओं से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से अनेक गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान संभव होती है, जिससे प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों का जीवन बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने युवाओं से समाजहित में आगे आकर रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, आयुष सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने जैसे प्रयासों से देश के करोड़ों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।

चिली पोटैटो बनाते समय कुक की कथित लापरवाही से लगी थी आग, गुबार उठते ही भाग निकला था नेगी

नई दिल्ली । दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग में 23 मौत के लिए पुलिस ने कुक केशव नेगी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कुक ने पूछताछ में बताया कि गुरुग्राम के रहने वाले विवेक अग्रवाल के परिवार के ऑर्डर पर चिली पोटैटो बनाते समय लापरवाही से आग लगी और वह भाग गया जिसकी वजह से छोटी सी आग ने भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया। अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट नहीं आने से इस थ्योरी पर सवाल भी उठ रहे है। कोई भी अधिकारी इस बारे में अपने नाम से बयान देने से बच रहा है। दक्षिण जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि गुरुग्राम निवासी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल के पिता राधेश्याम मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। विवेक अपनी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, मां प्रेमलता अग्रवाल, दो बेटी, मामा अशोक अग्रवाल और मौसी कमला अग्रवाल व मौसा के साथ उनका हालचाल जानने के लिए इसी होटल में ठहरे थे। होटल में ठहरे विवेक और उसके परिवार को अस्पताल जाना था। इन्होंने कुक केशव को आठ लोगों के लिए चिली पोटैटो बनाने के लिए बोला था। अमुक अधिकारी के मुताबिक केशव नेगी ने पूछताछ में बताया कि जैसे ही उसने फ्राईपैन से पोटैटो को मिक्स करने के लिए उछाला तो फ्राईपान ने आग पकड़ ली और भड़क गई। ऐसे में केशव नेगी के हाथ से आग लगा फ्राईपैन छूट गया। इससे रसोई में आसपास रखे तेल, अन्य सामान समेत ज्वलनशील पदार्थों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग विकराल हो गई। बता दें कि हादसे में अग्रवाल परिवार के पांच सदस्यों और तीन रिश्तेदारों समेत कुल 23 लोगों की मौत हो गई थी। ।

आग फैलते ही भाग खड़ा हुआ नेगी

पुलिस जांच में सामने आया कि आग फैलते ही केशव नेगी रसोई से भाग गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि उसने मैनेजर दिलीप को फोन किया था। हालांकि पुलिस उसके इस दावे की जांच कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर केशव नेगी ने आग बुझाने के क्यों प्रयास नहीं किए। क्या वह आग को बुझा नहीं पाया या फिर होटल में आग बुझाने वाले उपकरण काम नहीं कर रहे थे। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि आग काफी फैल गई थी। तभी होटल की लाइट काट दी गई। इससे होटल के प्रवेश द्वार समेत अन्य गेट ने काम करना बंद कर दिया। गेट लाइट से ऑटोमेटिक बंद व खुलते थे। पुलिस ने केशव नेगी को छह जून को गिरफ्तार किया था।

कुछ अनसुलझे सवाल

क्या आग लगने का सटीक कारण फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रमाणित हो चुका है, या पुलिस अपना नरेटिव इस हादसे में थोपना चाहती है?

निष्पक्ष नहीं होंगे अगले चुनाव- इंडिया ब्लॉक के नेताओं से राहुल की अपील- भाजपा को हराना आसान, एकजुट रहें

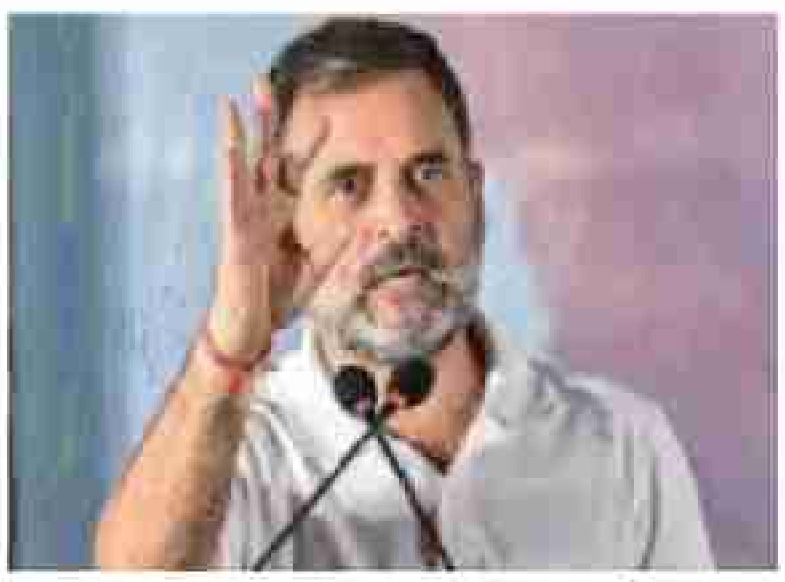

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हफ्ते की शुरुआत में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कहा कि जनता के आक्रोश को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले आम चुनाव तो पहले ही जीत लिए हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। इंडिया ब्लॉक की सोमवार की बैठक में उन्होंने सभी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सब मिलकर साथ खड़े हों और विरोध करें तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराना आसान है।

नीलकंठ की तरह आलोचनाओं को मुस्कराकर स्वीकार करूंगा

राहुल गांधी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वह सभी आलोचनाओं को स्वीकार करेंगे। उन्होंने नीलकंठ (शिव) का उदाहरण दिया और कहा कि वह भी उनकी तरह हर आलोचनाओं को सहेंगे और उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करेंगे, चाहे वह उनके या उनकी पार्टी के खिलाफ ही क्यों न हो। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर उस भाषण का वीडियो भी साझा किया। उन्होंने बैठक में करीब नौ मिनट का भाषण दिया था। इस बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुटता पर जोर दिया था।

इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या तय किया गया?

सोमवार को इंडिया ब्लॉक ने तय किया कि नीट और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी और कथित वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखा जाएगा।

अब हालात बदल चुके हैं

अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि उनका काम कांग्रेस पार्टी की किसी भी आलोचना का जवाब देना नहीं है, बल्कि सबको साथ जोड़ना है, चाहे कोई भी आलोचना क्यों न हो। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में भ्रम है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आरजेडी जैसे कई दल यह मानते हैं कि उनके पुराने राजनीतिक तरीके अभी भी काम करेंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा पर क्या आरोप लगाया?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने न्यायपालिका, प्रशासन, खुफिया एजेंसियां और यहां तक कि चुनाव आयोग जैसी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है।

कथित वोट चोरी को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि कई राज्यों के चुनावों में उन्हें पहले से अनुभव है कि कैसे नतीजे प्रभावित होते हैं और उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव जैसे कई नेता मानते हैं कि उनके चुनाव चोरी हुए हैं और उन्होंने विभिन्न स्तर पर शंका जताई। लेकिन उनका दावा है कि पूरी व्यवस्था प्रभावित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक प्रतिरोध की पार्टी है और उनका मकसद विपक्षी दलों के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि उन्हें एकजुट करना है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने 2024 का चुनाव हारा नहीं बल्कि जीता था और कुछ कारणों से राजनीतिक हालात बदल गए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक संस्थाएं और कमजोर होंगी, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का प्रभाव बढ़ा है।

ममता बनर्जी के खिलाफ हुई एफआईआर

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी पर लगभग दो महीने पुराने हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

कोलकाता पुलिस ने कथित नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया है. ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के मंच से कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ममता बनर्जी की इन टिप्पणियों से सांप्रदायिक नफरत भड़की. यह मामला बीएनएसकी धाराओं 196(1), 351(2) और 352 के तहत हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. खबरों के अनुसार, पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की है और मामले को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेज दिया है. वहीं अरुणाचल प्रदेश से सांसद और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए 27 मई 2026 को ममता बनर्जी के उस बयान पर चिंता जताई थी, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि ममता जी का ये अब तक का सबसे परेशान करने वाला और अपमानजनक बयान है.ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के मंच से कहा था, हम हैं, इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं. अगर हम यहां न होते, तो अब कोई खास समुदाय एक गुट बनाकर आपको घेरता, तो वे आपको एक सेकंड में खत्म कर देते. इससे पहले सांसद और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर दिए गए उनके आक्रामक बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है.

हार नहीं, यह कामयाबी की सीढ़ी- अमित शाह

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु भाजपा के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने राज्य में पार्टी को मजबूत करने और जमीन पर काम बढ़ाने को लेकर लंबी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों के लिए अभी से तैयारियां तेज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में हुई भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक की अध्यक्षता खुद अमित शाह ने की। बैठक में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालातों और पार्टी के प्रदर्शन पर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में शामिल एक सूत्र के मुताबिक, अमित शाह ने राज्य के नेताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु में भाजपा का जो मुख्य वोट बैंक है, वह कहीं नहीं गया है और पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। गृह मंत्री ने तमिलनाडु भाजपा इकाई को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हालिया चुनावी नतीजों को एक झटके या हार के रूप में बिल्कुल न देखें। इसके बजाय इन नतीजों को भविष्य की कामयाबी के लिए एक मजबूत सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य में संगठन को और मजबूत करने के लिए एक पूरा रोडमैप भी नेताओं के साथ साझा किया है। तमिलनाडु चुनाव में भाजपा ने अन्नाद्रमुक , पीएमके और एएमएमके जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुल 2.97 फीसदी वोट मिले और वह सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रही। इस कमजोर प्रदर्शन के बाद भी पार्टी का हौसला बुलंद है। बैठक में शामिल राष्ट्रीय सह-प्रभारी डॉ पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हम नई ऊर्जा के साथ तमिलनाडु की जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी पार्टी की इस ओपन-माइंडेड समीक्षा नीति की तारीफ की और कहा कि इससे नेताओं को आगे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन सहित राज्य के कई बड़े नेता मौजूद रहे।

कल्याण बनर्जी बड़े हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, टीएमसी में बगावत के बाद अभिषेक बनर्जी का बयान

कोलकाता।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में बड़ी टूट की आहट के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर कहा कि वह उनसे बड़े हैं और उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है। बनर्जी ने कहा कि वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा, कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े हैं। उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा।

सीआईडी की जांच पर क्या कहा?

जाली हस्ताक्षर मामले में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समन पर अभिषेक बनर्जी ने कहा, आप जानते हैं कि मुझे सीआईडी ने तलब किया था। मैं वहां साढ़े पांच घंटे तक रहा। मुझे 14 जून को फिर बुलाया गया है और मैं वहां जाऊंगा। मैं हमेशा इस तरह की जांच में सहयोग करता हूं। मुझे एक अन्य मामले में भी फिर से समन दिया जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो किसी और को नोटिस दे दें। लेकिन मैंने सुना कि वे इंतजार कर रहे थे। अगर वे ऐसे समय नोटिस देना चाहते हैं जब मैं घर पर नहीं हूं और किसी दूसरे व्यक्ति को नोटिस लेने की अनुमति भी नहीं है, तो उन्हें मेरे घर लौटने तक इंतजार करना होगा। मैं हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करता हूं। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान मेरे डीजे को लेकर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब सरकार बदल गई है और मेरे खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उकसावे वाले बयानों के लिए अमित शाह (केंद्रीय गृह मंत्री) के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए?

हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे

उन्होंने आगे कहा, मेरी पेशी को लेकर कई लोग सीआईडी से मिली जानकारी के आधार पर खबरें चला रहे हैं। इस मामले में जानकारी लीक किए जाने के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और मैं खुद कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा हूं। इस लड़ाई में हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आप हमें झुका नहीं सकते। हमें एजेंसियों से डर नहीं लगता। विधायकों और सांसदों को साथ लेकर टीएमसी को नहीं झुकाया जा सकता। आपने कहा था कि अन्नपूर्णा भंडार देंगे, लेकिन अब हालात अलग हैं। सीआईडी के अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंचने पर टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा, अभिषेक बनर्जी अपने मामलों पर खुद जवाब देने में सक्षम हैं। इस विषय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर कहा कि वह उनसे बड़े हैं और उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार है। बनर्जी ने कहा कि वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे।

नाविकों पर अमेरिकी हमले से भड़का भारत

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा और सख्त राजनयिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक दूत जेसन मीक्स को तलब किया। साउथ ब्लॉक में हुई इस बैठक के दौरान भारत ने अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर अपना विरोध दर्ज कराया। यह पूरा मामला ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में अमेरिकी नौसैनिक बलों की ओर से किए गए कथित हमलों से जुड़ा हुआ है। इन व्यापारिक जहाजों पर भारतीय नाविक सवार थे। खास बात यह है कि जेसन मीक्स को इससे पहले बुधवार रात को भी तलब किया गया था। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नागरिक जहाजों के खिलाफ इस प्रकार के घातक बल का उपयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राजनयिक वार्ता के दौरान अमेरिकी पक्ष को स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस तरह की हिंसक घटनाएं अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। यह क्षेत्रीय स्थिरता को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे नागरिक जीवन को कोई नुकसान पहुंचे।

अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत

बता दें कि इन अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई है। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अमेरिकी नौसेना ने भारतीय चालक दल वाले तीन जहाजों को निशाना बनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन हमलों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ये हमले अमेरिकी नौसेना की तरफ से हुए थे। भारत ने कहा कि इस तरह से नागरिकों की जान जाना पूरी तरह से टाला जा सकता था।

तीन जहाजों पर चार दिनों में हुआ हमला

अमेरिकी सेना ने इस हफ्ते एक के बाद एक तीन जहाजों को निशाना बनाया। पहला हमला आठ जून को पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर मारिलेक्स पर हुआ। इस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। यह जहाज पूरी तरह ठप हो गया, लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरा हमला 10 जून को पलाऊ के ही दूसरे टैंकर सेंटेबेलो पर हुआ। इस हमले में जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से तीन नाविकों की मौत हो गई। तीसरा हमला गुरुवार 11 जून को गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले टैंकर जलवीर पर हुआ। इस पर 20 भारतीय सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इनमें से दो जहाजों पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की ओर से प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं एक अन्य जहाज नियमों का पालन नहीं कर रहा था। यह अमेरिकी एजेंसी ईरानी और रूसी तेल बेचने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है।

अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ चढ़ावा चोरी! संजय राउत ने कहा- बीजेपी हर जगह कर रही डकैती

मुंबई ।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों की कथित हेराफेरी को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चीज की चोरी करती है, चाहे वह ईवीएम हो या भगवान राम को चढ़ाया गया दान। राउत ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपये गायब होना गंभीर मामला है और इसके लिए उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार जिम्मेदार है। संजय राउत ने बताया कि वे उद्धव ठाकरे के साथ जल्द ही अयोध्या जाएंगे और इस स्थिति के लिए भगवान राम से माफी मांगेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की थी। पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया है कि दान के करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि मंदिर प्रशासन सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।

अरविंद केजरीवाल की मांग- गोवा में 300 यूनिट तक मुफ्त मिले बिजली, दिल्ली-पंजाब मॉडल लागू हो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में बिजली दरों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि गोवा में देश की सबसे ऊंची बिजली दरों में से एक लागू है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा के एक मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली और पंजाब की तरह गोवा में भी प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए। केजरीवाल ने कहा कि आम लोगों को बढ़ती बिजली दरों से राहत देने के लिए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। मुफ्त बिजली के अलावा उन्होंने गोवा में हर परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की सम्मान राशि का भी वादा किया है।

ट्रम्प बोले- ईरान के साथ आज जंग खत्म हुई- वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे; ईरान बोला- अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। एक वर्चुअल रैली में ट्रम्प ने अपने समर्थकों से यह बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।

ईरान ने ट्रम्प के इस दावे को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि शांति समझौते पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने नई डील को मंजूरी कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इसमें शामिल होंगे।

राजग सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा माहौल बनाया कि वे अपनी पूरी क्षमता दिखा सकें - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

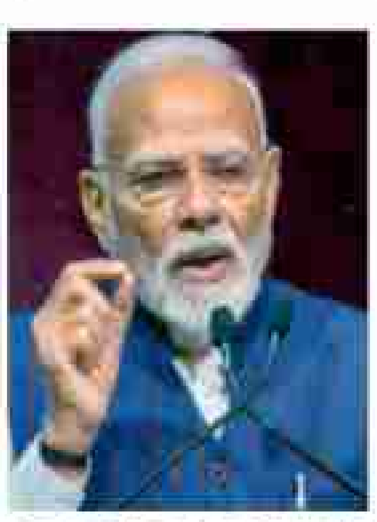

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के प्रयास सम्मान, अवसर और सशक्तीकरण पर आधारित हैं और इनसे ऐसा माहौल बनाने में मदद मिली है जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता दिखा सकती हैं तथा राष्ट्र निर्माण में और अधिक मजबूती से योगदान दे सकती हैं। मोदी ने कहा कि राजग सरकार ने पिछले 12 वर्ष में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और यह विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, राजग सरकार के प्रयास सम्मान, अवसर और सशक्तीकरण पर आधारित हैं। इनसे ऐसा माहौल बनाने में मदद मिली है जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता दिखा सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में और अधिक मजबूती से योगदान दे सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह देखकर विशेष खुशी होती है कि भारत की नारी शक्ति विज्ञान, अंतरिक्ष और नवोन्मेष जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अवसरों के नए रास्ते खोल रही है

और देशभर में विकास की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है। उनका दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 को शुरू हुआ तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और निर्णायक जीत के बाद उन्होंने नौ जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ ली। मोदी ने 1952 के आम चुनावों के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में रहने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिन के रिकॉर्ड को भी बुधवार को तोड़ दिया। नेहरू 1947 से 1952 तक अंतरिम सरकार के प्रमुख रहे थे क्योंकि 1952 तक चुनाव नहीं हुए थे।